

**राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
उत्तराखण्ड राज्य इकाई, देहरादून**

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार**

मई - 2023

ऑनलाइन लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य सभी सरकारी विभागों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकारी समितियों, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में खातों की आंतरिक और वित्तीय लेखापरीक्षा की सुविधा प्रदान करना है।



2 वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की गई



200+ आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई



40+ स्थानीय निकायों का ऑडिट पूरा हुआ



326+ ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई

पंचायतों,
यूएलबी और
विभागों के
ऑडिट रिकॉर्ड
का उचित
रखरखाव

खातों के
ऑनलाइन और
ऑफलाइन ऑडिट
की सुविधा

पारदर्शिता और
जवाबदेही में
सुधार



सूचना पत्र भरना



ऑनलाइन प्रणाली पर प्रवेश और विकास सम्मेलन विवरण



ऑडिट टीम द्वारा जुटाए गए हाफ मेमो मार्जिन का जवाब दें और दस्तावेज अपलोड करें



प्रशासनिक विभाग के प्रत्येक सचिव और विभागाध्यक्ष के लिए डैश बोर्ड



ड्राफ्ट रिपोर्ट अपलोड दस्तावेजों में ऑडिट टीम द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब।



लेखापरीक्षा टीम द्वारा उठाए गए मुद्दों पर समेकित रिपोर्ट वाले विभागों के लिए बेहतर वित्तीय और आंतरिक नियंत्रण



सभी विभागों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की निगरानी और प्रबंधन



रीयल टाइम डेटा शेयरिंग



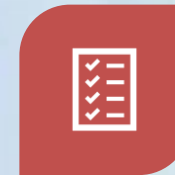
वास्तविक समय पर विभिन्न लेखापरीक्षा टीम को कार्य देने का आसान प्रबंधन और अनुसूची



वित्तीय वर्ष के आधार पर रिपोर्टों का आसान संकलन



विभिन्न विभागों में विभिन्न लेखापरीक्षा दल के कार्य प्रगति की निगरानी करना



वित्तीय वर्ष वार नंबर का आसान विश्लेषण। विभिन्न विभागों में किए गए ऑडिट के



ऑडिट टीम द्वारा कार्य आउटपुट रिपोर्ट को ऑनलाइन जमा करना या अपलोड करना

जीपीएफ ऑनलाइन सेवाएं

1. जीपीएफ ऑनलाइन सेवा
2. जीपीएफ एसएमएस (पुश) सेवा
3. जीपीएफ एसएमएस (पुल) सेवा
4. मोबाइल पंजीकरण
5. जीपीएफ अंतिम भुगतान स्थिति
6. ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
7. पेंशन की स्थिति
8. सुलह प्रतिक्रिया

हितधारक

वित्त विभाग

सचिव

विभागों के
प्रमुख (एचओडी)

आहरण और
संवितरण
अधिकारी
(डीडीओ)

कोषागार / उप
कोषागार
अधिकारी

राज्य सरकार के
कर्मचारी

कोषागारों/उप
कोषागारों से पेंशन
आहरित करने वाले
पेंशनभोगी

महालेखाकार
उत्तराखण्ड

मोबाइल एप्लिकेशन

जीपीएफ ऑनलाइन उत्तराखंड

GOVERNMENT SERVICE TO EMPLOYEE (G2E)



उत्तराखण्ड सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि
(GPF) संबंधित विभिन्न सूचनाओं की जानकारी देता है!

कर्मचारियों को जीपीएफ की शेष राशि, वार्षिक जीपीएफ
विवरण (2003 से आज तक) देखने की सुविधा!

जीपीएफ दिशानिर्देश, अंतिम जीपीएफ स्टेटमेंट आदि।))

ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकता है!

बहुभाषी जानकारी भी उपलब्ध कराता है!

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस के तरफ बढ़ते कदम।
इसे डाउनलोड कर सकते हैं -



प्ले स्टोर

Designed and Developed by **NIC** NATIONAL
INFORMATICS
CENTRE

Slide Number 3



Home About Us Contact Us Login

Women Empowerment & Child Development

Govt of Uttarakhand

Projects

105

Sector

597

Anganwadi Centres (AWC)

20067

एम.आई.एस. हितधारक

सचिव

निदेशक

ज़िला

ब्लॉक

आंगनवाड़ी
केंद्र

सुविधाएँ

सचिव स्तर, निदेशक स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और आंगनवाड़ी केंद्र स्तर लॉगिन

KPI (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) प्रत्येक लॉगिन पर आधारित डैशबोर्ड

प्रत्येक लॉगिन पर लचीली और मजबूत रिपोर्टिंग

निदेशक स्तर पर श्रेणी प्रबंधन एवं बजट आवंटन की सुविधा।

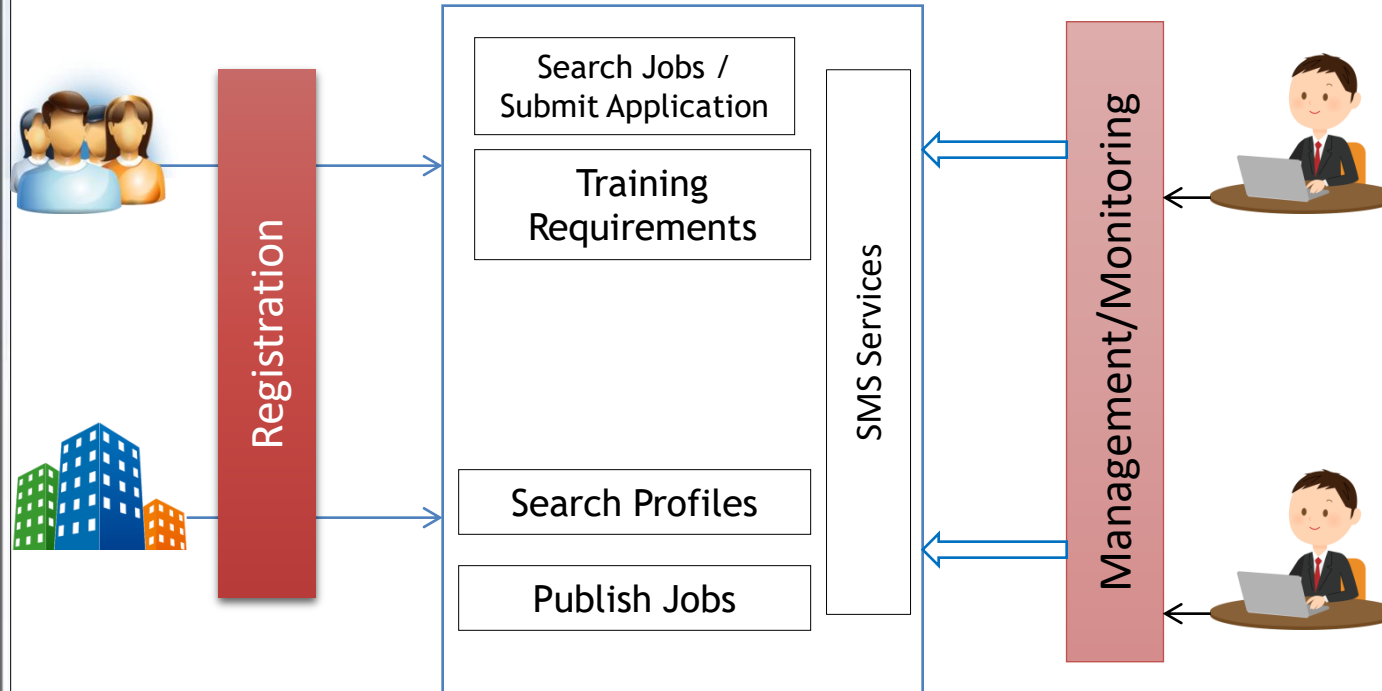
निदेशक स्तर द्वारा आवंटित बजट ब्लॉक लॉगिन पर दिखाई देता है और यह एप्लिकेशन निर्दिष्ट श्रेणियों के तहत विभिन्न आंगनवाड़ियों को बजट आवंटित करने की सुविधा प्रदान करता है।

एमआईएस आवेदन के तहत आंगनवाड़ी लॉगिन, माता समिति और व्यक्तिगत खाता व्यय विवरण का प्रबंधन कर सकते हैं

आंगनवाड़ी केंद्र अपने बैंक विवरण और उनकी मातृ समिति के गठन के प्रावधान का प्रबंधन भी कर सकते हैं।

BASIC ARCHITECTURE

HOPE Portal



Vacancy Dashboard

District	Sector			
ALMORA	DEHRADUN	HARIDWAR	NAINITAL	PAURI GARHWAL
5 VACANCIES	148 VACANCIES	1023 VACANCIES	250 VACANCIES	1 VACANCIES
TEHRI GARHWAL	UDHAM SINGH NAGAR			
5 VACANCIES	463 VACANCIES			

सुविधाएँ

नियोक्ता डेटा

पंजीकृत नियोक्ताओं का जिलावार सारांश
 ✓ पंजीकृत नियोक्ताओं का सत्यापन करें
 ✓ पंजीकृत नियोक्ताओं की विस्तृत जानकारी

रिपोर्ट

✓ सारांश रिपोर्ट
 ✓ तिथिवार सारांश रिपोर्ट
 ✓ जिलेवार कुशल सारांश रिपोर्ट
 ✓ क्षेत्रवार आवेदकों की रिपोर्ट
 ✓ पैरामीटरयुक्त रिपोर्ट
 ✓ कीवर्ड आधारित जॉब रोल सर्च

बाहरी डेटा रिपोर्ट

प्रवासियों की रिपोर्ट
 पीएमकेवीवाई रिपोर्ट

उपयोगिताये

मोबाइल नंबर अपडेट करें
 रिक्तियों को संशोधित करें

मास्टर डेटा प्रबंधन

नौकरी क्षेत्रों का प्रबंधन करें
 कार्य भूमिकाएं प्रबंधित करें योग्यता विषय/ट्रेड प्रबंधित करें

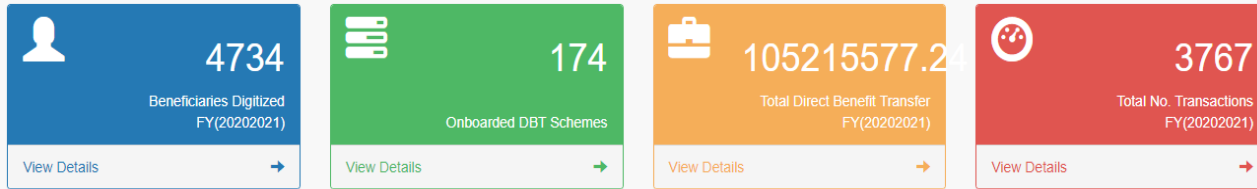
प्रतिक्रिया/सहायता

प्रतिक्रिया देखें
 प्रतिक्रिया
 प्रतिक्रिया रिपोर्ट

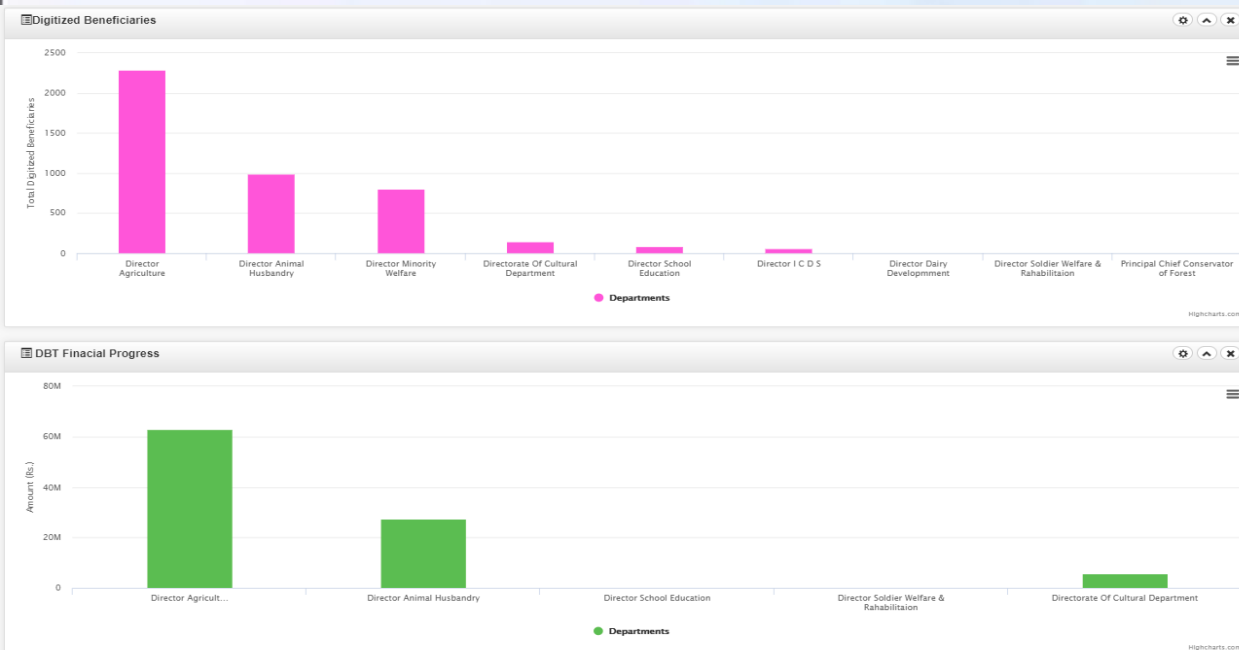
डीबीटी एमआईएस उत्तराखंड राज्य के विभिन्न विभागों के लिए लाभार्थियों की सूचना प्रणाली के पूर्ण प्रबंधन के लिए एक साझा मंच प्रदान करने की एक पहल है, जो राज्य के साथ-साथ केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लाभान्वित हुए हैं।

Total No. of Farmers Registered :- 15381

Total Direct Benefit Transfer(Cumulative) :- Rs.105215577.24



भौतिक और वित्तीय प्रगति



डीबीटी एमआईएस साइलेंट विशेषताएं

प्रणाली

उत्तराखण्ड के सभी विभागों के लिए एकीकृत मंच।

आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्तर अर्थात राज्य, जिला, डीडीओ एवं स्कूल स्तर आदि पर प्राधिकरण सृजित करने का प्रावधान।

राज्य और केंद्रीय डीबीटी पोर्टल के साथ एकीकरण शामिल किया जाएगा

भूमिका

एकीकृत विभागों के निदेशालय स्तर पर डीबीटी बजट प्रबंधन का प्रावधान।

विभाग की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्तरों पर डीबीटी लाभार्थियों के मूल और बैंक विवरण का डिजिटाइजेशन।

प्रत्येक माह के लिए लाभार्थी वार डीबीटी व्यय विवरण लिखना।

रिपोर्टिंग

विभिन्न प्राधिकरण स्तरों पर मजबूत और लचीली रिपोर्टिंग संरचना।

भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए KPI (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) आधारित डैशबोर्ड इंटरफ़ेस सिस्टम

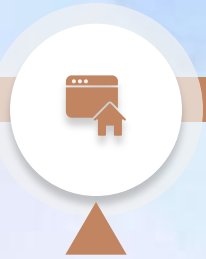
आई.एफ.एम.एस. के मॉड्यूल

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1 Payroll | 13 Research Management |
| 2 Human Resource | 14 Revolving Fund |
| 3 Budget Allotment | 15 Electricity Management |
| 4 Court Case | 16 Outsourcing(LWO) Mgt. |
| 5 Letter Monitoring | 17 Employee Corner |
| 6 Payments | 18 Manage Circular |
| 7 DSW | 19 Account Section |
| 8 House Allotment | 20 Hostel Management |
| 9 Finance Management | 21 College of Technology |
| 10 Assets Management | 22 Guest House Mgt. |
| 11 Cash Receipt | 23 Hospital Management |
| 12 Farms | 24 Krishi Vigyan Kendra(KVK) |
| 25 Student Ledger/Fee Mgt. | |

प्रमुख आकर्षण

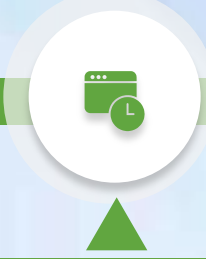
- 53 विभागों/कार्यालयों, 9-केवीके केंद्रों और 21-एआईसीआरपी परियोजनाओं का बजट आवंटन और बिल प्रसंस्करण
- तीन भुगतान गेटवे एकीकरण
- सीपीएस के लिए एनएसडीएल के साथ एकीकरण
- एसएमएस एकीकरण
- पीएफएमएस के अनुसार अनुकूलित
- बिजली के बिल के लिए Android आवेदन
- लॉगिन आईडी के साथ 4500 से अधिक छात्र और 2300 कर्मचारी

सीएम विवेकाधीन सिस्टम



- आवेदन डिजिटल और सीएम / मंत्री एस / एमएलए द्वारा अनुशंसित और सीएम कार्यालय अनुभाग -3 द्वारा संसाधित किया गया।
- आवेदनों की एक श्रृंखला/गुच्छा डिजिटाइज़ किया जाता है और प्रत्येक आवेदन की विशिष्ट पहचान के बाद सीआर प्रिंट किया जाता है।
- संसाधित सीआर पर संबंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और सीआर एक फाइल में बंध जाएगा।
- फाइल अनुमोदन के लिए अनुभाग से उच्च स्तर के अधिकारियों के पास जाती है और संबंधित अनुभाग में वापस आती है।
- फाइल के अनुमोदन के बाद, GO जनरेट होता है और बिल बनाने के लिए CM कार्यालय के सेक्शन - 6 में जाता है।
- कोषागार में बिल जमा करने के बाद कोषागार द्वारा बिल के विरुद्ध चेक जारी किया जाता है।
- उसके बाद स्वीकृत लाभार्थियों को राशि वितरित करने के लिए डीएम / अस्पतालों के पक्ष में ड्राफ्ट सलाह तैयार की जाती है और ड्राफ्ट सलाह के खिलाफ बैंक ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक को प्रस्तुत किया जाता है।
- राशि संबंधित को डीएम/अस्पतालों के माध्यम से वितरित की जाती है।

सीएम घोषणा सिस्टम



- मुख्यमंत्री द्वारा घोषित घोषणाएं, एक विशेष विभाग या कई विभागों से संबंधित होती हैं जो आम जनता या सरकारी विभाग के लिए हैं ! इस प्रणाली के तहत इन सारी घोषणाओं को सिस्टम में अंकित किया जाता है !
- इन सारी घोषणाओं पर प्राथमिक कार्यवाही मुख्यमंत्री कार्यालय के सेक्शन-4 के द्वारा किया जाता है
- घोषणाओं को अनुभाग कार्यालय में प्राप्त करने के बाद, ई-गवर्नेंस सिस्टम में डिजिटल किया जाता है।
- आगमिक कार्यवाही के लिए अनेक विभागों से संबंधित घोषणाओं को संबंधित विभाग के पास भेजा जाता है | जिसकी अंकन सिस्टम में किया जाता है |
- एक बार चिह्नित किए गई घोषणाओं के संसाधित होने के बाद, संबंधित विभागों द्वारा उत्तर प्राप्त को सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाता है , सिस्टम में पूर्ण (पूर्ण) या लंबित (लंबित) की स्थिति के साथ घोषणा का पूर्ण ब्यौरा अंकित किया जाता है |
- सीएम घोषणा सरल, पारदर्शी प्रणाली हैं जिसके तहत किसी भी स्थिति की किसी भी घोषणा की जानकारी आसानी से हासिल की जा सकती है |

मुख्यमंत्री पत्र निगरानी प्रणाली



- सीएम कार्यालय के मुख्य रूप से तीन सेक्शन (1, 2 और 5) में लेटर मॉनिटरिंग संबंधित कार्य संसाधित किए जाते हैं।
- पत्र सभी वर्गों को डाक या हाथ से प्राप्त होते हैं।
- CM कार्यालय के सेक्शन -1 ने केवल V.I.P पत्र को संभाला।
- प्राप्त पत्र डिजिटाइज़ सिस्टम में किया जाता है और डेटाबेस में सहेजा जाता है और एक यूनिक पत्र संख्या उत्पन्न होती है।
- पत्र को सम्बंधित अधिकारी को भेजा जाता है |
- सिस्टम में स्टेटस (पूर्ण), लंबित (लंबित) के साथ संबंधित पत्रों की स्थिति अपडेट की जाती है।
- पत्र का अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर, अनुभाग में वापस आ जाता है और फिर से डेटाबेस में अपडेट किया जाता है।
- मुख्यमंत्री कार्यालय का सेक्शन -2 केवल सामान्य पत्रों को संभालती है और बाकी की प्रक्रिया ऊपर की तरह ही होती है।
- मुख्यमंत्री कार्यालय का सेक्शन -5 जनता के मुद्दों से सम्बन्धित पत्रों को संभालती है और बाकी प्रक्रिया उपरोक्त के समान है।

मुख्यमंत्री कार्यालय सुइट



- यह विवेकाधीन, घोसना और लेटर मॉनिटरिंग एप्लिकेशन के लिए विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड है।
- इस एप्लिकेशन में विभिन्न मापदंडों के आधार पर ड्रिल डाउन कार्यक्षमता है।
- इस एप्लिकेशन के पास साल के हिसाब से फिल्टर के साथ सिंगल स्क्रीन में सभी डेटा की गिनती है।

उत्तराखण्ड का सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल (eSPAN 2.0) राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को मौद्रिक लाभों के ई-भुगतान के लिए पारदर्शी कार्यप्रवाह, वेब-आधारित प्रक्रिया स्वचालन की सुविधा प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 से
ऑनलाइन वेब
आधारित : कार्यप्रवाह
आधारित प्रणाली

आवेदनों का ऑनलाइन
प्रस्तुतीकरण, त्रैमासिक पेंशन
प्रसंस्करण, सीटीएस और
एनएसएपी पोर्टलों के लिए
उचित लिंकेज के साथ तत्काल
सूचना प्रसार

डीबीटी प्रक्रिया को सुगम
बनाता है - खाता आधारित

सुविधा लगभग। राज्य
की आबादी का 7%
(समाज के जरूरतमंद
और कमजोर वर्ग)

12 पूरी तरह से और
अर्ध-राज्य वित्त पोषित
योजनाओं के लिए
त्रैमासिक/मासिक
ऑनलाइन पेंशन
प्रसंस्करण की सुविधा

Key Statistics

ऑनलाइन पेंशन योजनाओं की कुल
संख्या- 12

कुल पंजीकृत पेंशनरों की संख्या -
8 लाख +

कुल डीबीटी लाभार्थी 7.5 लाख + और
हस्तांतरित राशि रुपये है। 1000 +
करोड़ सालाना



Tangible Contribution in Governance

01

एक ही व्यक्ति को
अनेक लाभों से
बचाता है

02

पारदर्शिता- नकली,
डुप्लीकेट और योग्य
नहीं पेंशनरों और
बिचौलियों का
सफाया कर दिया

03

डेटा की आसान
निगरानी के साथ
इलेक्ट्रॉनिक
एकीकरण के रूप में
प्रामाणिक डेटा पर
निर्णय लिए गए हैं

04

प्रत्यक्ष ई - भुगतान और
समय पर संवितरण
सीटीएस (कोर ट्रेजरी
सिस्टम) के साथ
एकीकरण

05

G2C 'नागरिक
सेवाएं'- पेंशन पासबुक
विवरण और स्थिति
की जानकारी का
त्वरित सूचना प्रसार

06

ग्रीन ई-सरकार
ऑनलाइन रिपोर्टिंग
के साथ 8 लाख से
अधिक नागरिकों का
एक डिजिटल डेटाबेस

प्रमुख विशेषताएँ

वेब सक्षम प्रणाली

हर साल मुख्य और पूरक बजट
तैयार करना

उत्तराखंड बजट मोबाइल ऐप
द्वारा बजट भी एक्सेस किया
गया।

बजट ई-बुक द्वारा प्रस्तुत बजट

"आपका बजट आपके सुझाव" ने
बजट तैयार करने के लिए एक
प्रमुख रोल लागू किया

ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर

वित्तीय वर्ष के आधार पर रिपोर्ट
का चित्रमय प्रतिनिधित्व

विश्व बैंक DEBT प्रबंधन के लिए
मदद करता है

उत्तराखण्ड आबकारी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल उत्तराखंड राज्य के हितधारकों को विभिन्न आबकारी लाइसेंस, ई-पास, ई-परमिट और ई-भुगतान लाभों के लिए पारदर्शी वर्कफ़्लो, वेब-आधारित प्रक्रिया स्वचालन की सुविधा प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2010-11
से ऑनलाइन वेब
आधारित प्रणाली

विभिन्न प्रकार के उत्पाद
शुल्क लाइसेंस के लिए
ऑनलाइन आवेदन जमा
करना, विभिन्न प्रकार की
आपूर्ति श्रृंखला पास और
परमिट आदि की ऑनलाइन
पीढ़ी।

सीटीएस (कोर ट्रेजरी
सिस्टम) के साथ
एकीकरण

लगभग उत्पन्न करने
में योगदान। राज्य के
राजस्व का 7.5%

हितधारकों के लिए
ऑनलाइन आयात
परमिट, परिवहन पास,
स्टॉक की उपलब्धता
की सुविधा

प्रमुख सांख्यिकी

आबकारी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन
सेवाओं की कुल संख्या – 16

क्यूआर कोड आधारित
परमिट/पास। अधिकारी पास/परमिट
की प्रामाणिकता को ट्रैक कर सकते
हैं

बुद्धिमान और वास्तविक समय की
रिपोर्ट। प्रदर्शन और दक्षता में सुधार।

प्रभावी राजस्व जुटाना

शासन में मूर्त योगदान

01

बेहतर इन्वेंटरी
प्रबंधन

02

अपने हितधारकों के साथ
विभाग और उसके
व्यवसाय को पारदर्शिता
प्रदान करना

03

डेटा की निगरानी के साथ
दैनिक मिलान और
राजस्व अभिलेखों को
सक्षम करना.

04

प्रत्यक्ष ई - भुगतान
सीटीएस (कोर ट्रेजरी
सिस्टम) के साथ एकीकरण

05

G2C 'नागरिक सेवाएं'-
आवेदनों की तत्काल
सूचना और समय पर
स्थिति और अंतिम
प्रमाणपत्र बनाना

06

ग्रीन ई-सरकार
विभाग के 10 हजार+
लाइसेंसधारियों का
एक डिजिटल
डेटाबेस। ऑनलाइन
रिपोर्टिंग के साथ

राज्य लोक उपापन पोर्टल का कार्यान्वयन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मार्गदर्शित

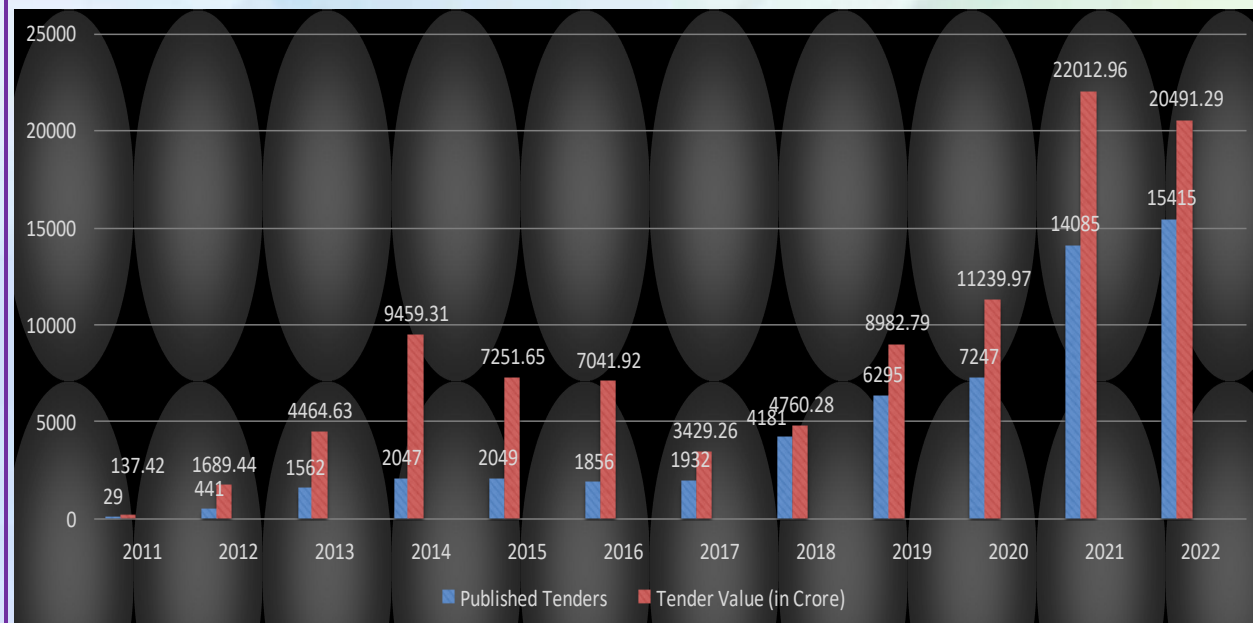
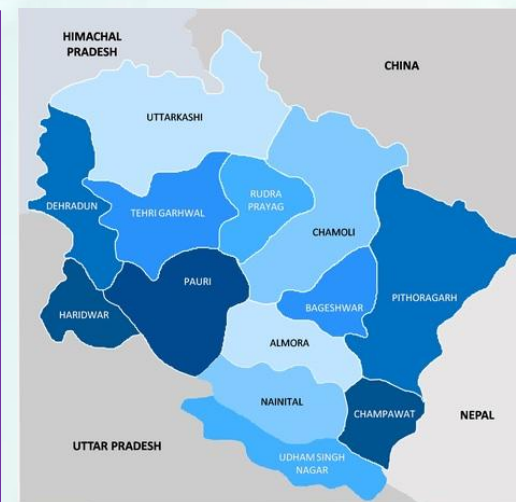
कुल निविदाएं – 62485 [जनवरी 2023 तक]
निविदाओं का मूल्य – ₹ 118554.44 करोड़
मासिक औसत – 1285 निविदाएं / कीमत - 1707.61 करोड़ रुपया

राज्य पोर्टल की मुख्य विशेषताएं(<https://uktenders.gov.in>)

- शासनादेश संख्या: 102/XXVII(7)/2011, दिनांक: 6 जुलाई 2011, 9th नवम्बर 2011 से प्रभाव के साथ.
- स्टेट पोर्टल में सभी संगठनों के निविदाओं की रियल टाइम सूचना
- विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, एवं एस.टी.क्यू.सी. द्वारा प्रमाणित एवं परीक्षित
- रिवर्स बोली और निविदाओं में एम.एस.एम.ई. एवं नए बिजनेस के लिए वरीयता
- वैश्विक निविदाएं
- निविदा-व-नीलामी
- उत्तराखण्ड में पोर्टल से 95-97% खरीदारी

कार्यान्वयन की स्थिति

संगठन – 1,086
विभाग उपयोगकर्ता – 1,993
बोली लगाने वाला/ठेकेदार – 18,151
बोली प्राप्त हुई – 1,73,843





StarBus*

एकीकृत बस सेवा बुकिंग पोर्टल

<https://starbus.nic.in>

प्रमुख घटक

- ❖ बस बुकिंग और रद्दीकरण
- ❖ चालक दल प्रबंधन
- ❖ फ्लीट प्रबंधन
- ❖ कार्यशाला एवं स्टोर प्रबंधन
- ❖ बस पास
- ❖ कूरियर सेवा और चार्टर्ड बस बुकिंग सेवा

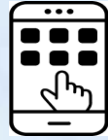
रा० सू० वि० केंद्र का कॉपीराइट उत्पाद जो कि परिवहन विभाग/निगम की बस सेवाओं से संबंधित कार्यों के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव की प्रक्रियाओं के सम्पूर्ण ऑटोमेशन हेतु Work Flow आधारित प्रणाली है

सेवा प्रदान करने हेतु माध्यम



वेब पोर्टल

यात्री | प्रबंधन | अन्य



मोबाइल ऐप

यात्री | कंडक्टर | ईबीटीएम | टी आई



एजेंट

अधिकृत | Third Party जैसे कि RedBus आदि



सेवा वितरण केंद्र

सार्वजनिक सेवा केंद्र | बुकिंग काउंटेर्स

मुख्य विशेषताएं

- ❖ Cloud Enabled प्रणाली
- ❖ प्रतिकृति हेतु त्वरित उपलब्धता
- ❖ 100% Configurable
- ❖ बहुभाषी
- ❖ सभी हितधारकों के लिए स्वयं सेवा पोर्टल
- ❖ डिजिटल वॉलेट/पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेशन
- ❖ यात्रा के दौरान यात्री द्वारा Alert/ शिकायत भेजने की सुविधा एवं कंट्रोल रूम द्वारा शिकायत का त्वरित समाधान
- ❖ अतिरिक्त राजस्व अर्जन हेतु निजी बसों की सेवाओं को पोर्टल से जोड़ने की सुविधा
- ❖ सभी मेक और मॉडल हेतु पूर्णतया Configurable Android आधारित EBTM ऐप
- ❖ Rate my service, Track my bus, Wallet, Reward Point, Instant Refund Status आदि सुविधाओं से युक्त प्रोडक्ट

मुख्य विशेषताएं

उत्तराखंड में 2013 से सफलतापूर्वक क्रियान्वित है

एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के रूप 2019 से अब तक 8 राज्यों में क्रियान्वित है

अब तक 65 लाख से अधिक टिकट

दैनिक 5500 से अधिक Seats की बुकिंग

रोजाना 2000 से अधिक बस सेवाओं का सञ्चालन

अब तक 55000 से अधिक बस पास जारी

ई-मंत्रिमण्डल

<https://ecabinet.nic.in>

मंत्रिमंडल बैठकों से संबन्धित कार्यों को ऑनलाइन करने, Work flow को Automate करने, कागज की खपत को काम करने हेतु वर्चुअल मीटिंग्स आदि आधुनिक सेवाओं से युक्त रा० सू० वि० केंद्र का कॉपीराइट उत्पाद

प्रमुख घटक



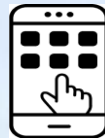
गोपन पोर्टल

कैबिनेट से संबंधित गोपनीय मामलों के लिए गोपन विभाग तक सीमित पहुंच



ई-मंत्रिमंडल पोर्टल

कभी भी, कहीं भी के आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्यों, विभागीय सचिवों एवं अन्य हितधारकों हेतु सूचना की त्वरित उपलब्धता



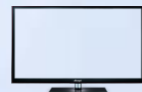
बैठक दिवस प्रबंधन प्रणाली

बैठक के प्रबंधन हेतु विकसित प्रणाली



प्रतीक्षालय सूचना प्रणाली

सचिवों/अधिकारियों के लिए प्रतीक्षालय प्रबंधन प्रणाली



कार्यान्वयन निगरानी प्रणाली

Unique Features

Security (Push & Pull)

Confidentiality (Restricted access)

Keep All Informed (Share Information)

Effective follow-up for good governance

Less Paper System

Integrated with Bharat VC

Easy to Use - To be integrated with eOffice

Bilingual, Self Configurable

DR Setup for Business Continuity

सफलता संकेतक

- ✓ मुख्यमंत्री, उत्तराखंड द्वारा जनवरी 2020 में **प्रथम ई-मंत्रिमण्डल बैठक के साथ उद्घाटन**
- ✓ ई-मंत्रिमण्डल के माध्यम से **90 से अधिक** बैठकों का सफल आयोजन
- ✓ कागज रहित प्रणाली के चलते औसतन **तीन बैठक पर एक वृक्ष की बचत**
- ✓ Covid19 के दौरान दूरस्थ स्थानों से मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से **मंत्रिमण्डल बैठक में virtual प्रतिभाग**
- ✓ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में लागू एवं सिक्किम, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा में प्रगति पर

प्रभाव और लाभ

- ❖ **हरित सचिवालय.....** पर्यावरण का संरक्षण
- ❖ सूचना की त्वरित उपलब्धता होने के कारण बैठक आयोजन के अंतिम क्षण तक वांछित सूचना प्राप्त हेतु की जाने वाली **भागदौड़ अब और नहीं**
- ❖ मंत्रिमण्डल के निर्णयों के समयबद्ध **क्रियान्वयन का प्रभावी अनुश्रवण**
- ❖ प्रौद्योगिकी के उपयोग के परिणामस्वरूप **सुशासन में वृद्धि**
- ❖ डिजिटल संस्थागत मेमोरी

इको टूरिज्म

वन विभाग की विभिन्न सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग हेतु पारदर्शी एवं आसान माध्यम

2021 से

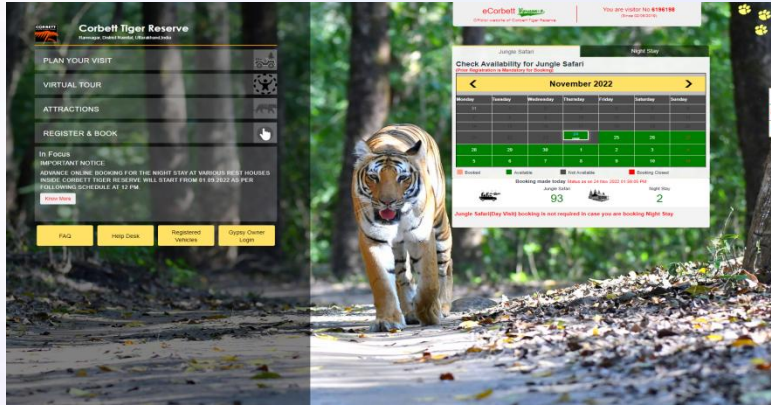
eCorbett 2.0

<https://corbtonline.uk.gov.in>

- ❖ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एकीकृत पोर्टल
- ❖ जंगल सफारी और रात्रि विश्राम हेतु बुकिंग
- ❖ गाइड और जिप्सियों का ऑटो आवंटन
- ❖ पार्क में पर्यटकों के भ्रमण की निगरानी हेतु प्रहरी ऐप
- ❖ कॉर्बेट नेचर गाइड मोबाइल ऐप

भविष्य में किये जाने वाले संभावित कार्य

- ✓स्मार्ट काउंटर
- ✓स्मार्ट गेट्स
- ✓पार्क में भ्रमण के लिए गयी जिप्सी मूवमेंट ट्रैकिंग
- ✓ऑटो रिफंड पोस्टिंग ... और भी बहुत कुछ



सितंबर 2021 में
उद्घाटन किया
गया

पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली

<https://mountaineering.uk.gov.in>

- ❖ पर्वतारोहण के लिए ऑनलाइन अनुमति
 - ❖ आईएमएफ, वन विभाग, अन्य सम्बन्धी विभागों एवं पर्वतारोहियों हेतु एकीकृत प्रणाली
 - ❖ आईएमएफ द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क का ऑनलाइन भुगतान
 - ❖ वन विभाग द्वारा आईएमएफ से प्राप्त ऐप्लिकेशन्स का ऑनलाइन अनुमोदन
 - ❖ पर्वतारोहियों हेतु परमिट डाउनलोड करने की ऑनलाइन सुविधा
 - ❖ डीएफओ द्वारा अभियान रिपोर्ट का ऑनलाइन प्रेषण
- भविष्य में किये जाने वाले संभावित कार्य
- पर्वतारोहियों, डीएफओ, चेकपोस्ट और अन्य हितधारकों के लिए मोबाइल ऐप



अक्टूबर 2022 में
उद्घाटन किया
गया

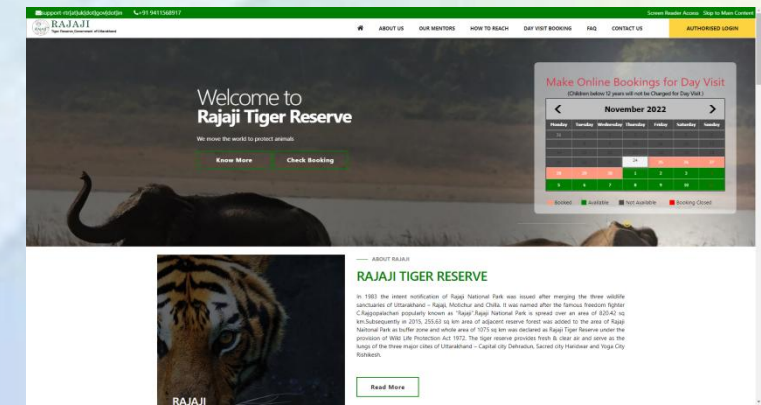
राजाजी टाइगर रिजर्व

<https://rajajitigerreserve.uk.gov.in>

- ❖ राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में समस्त जानकारी की एक ही स्थान पर उपलब्धता
- ❖ पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए ऑनलाइन सेवाएं
- ❖ केवल 3 सरल चरणों में जंगल सफारी और डे विजिट की बुकिंग
- ❖ काउंटर आधारित बुकिंग

भविष्य में किये जाने वाले संभावित कार्य

- ✓काउंटर बुकिंग को लाइव किया जाना
- ✓पर्यटकों हेतु मोबाइल ऐप
- ✓प्रशासन के लिए मोबाइल ऐप

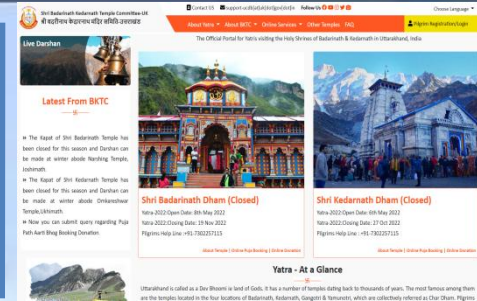


2013 से सेवा में

भविष्य में किये
जाने वाले कार्य

नंदा देवी बायोस्फीयर के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली और इकोटूरिज्म के लिए एकीकृत पोर्टल को Go Live किया जाना

<https://badrinath-kedarnath.gov.in>



तीर्थयात्रियों
के लिए
ऑनलाइन
सेवाएं

2019 से सेवा में
लगभग 8 करोड़
राजस्व

यात्रा सम्बंधित सूचना की एक ही स्थान पर उपलब्धता

कोविड-19 में कड़े यात्रा प्रतिबंधों के दौरान
ऑनलाइन पूजा, प्रसाद और यात्रा पंजीकरण

ऑनलाइन पूजा बुकिंग और दान

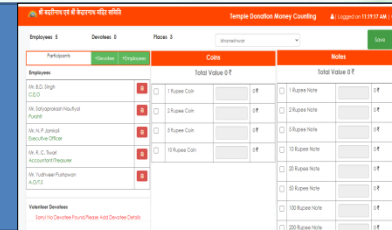
राज्य के सभी मंदिरों में
लागू किया जा सकता है

काउंटर ऑटोमेशन

- ✓ काउंटर आधारित पूजा बुकिंग, प्रसाद और दान
- ✓ लेखा प्रणाली और मंदिरों के लिए रिपोर्ट
- ✓ राजस्व संग्रहण की त्वरित सूचना हेतु वेबपोर्टल के साथ Integration

थाली भेंट काउंटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम

- ✓रीयलटाइम डेटा कैप्चर
- ✓राजस्व संग्रहण की त्वरित सूचना
- हेतु वेबपोर्टल के साथ Integration



तोशखाना

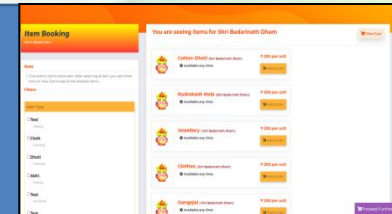
द शॉपिंग कार्ट

- ✓ भगवान को अर्पित वस्तुओं के लिए सूची प्रबंधन प्रणाली
- ✓ तीर्थयात्रियों विशेषकर जो धाम की यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए वस्तुओं की ऑनलाइन क्रय करने की सुविधा

POS आधारित ऑफलाइन डोनेशन संग्रह

वीआईपी दर्शन

अनुमति प्रणाली



मोबाइल ऐप

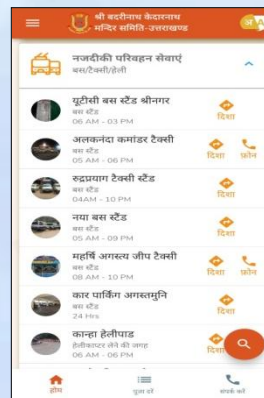
यात्री ऐप

तीर्थयात्रियों हेतु

- तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा गाइड, गूगल मानचित्र सेवा से लैस

- सार्वजनिक सुविधाओं , एटीएम, पुलिस आदि की जानकारी की ऑफलाइन उपलब्धता

-पूजा ब्रकिंग और दान



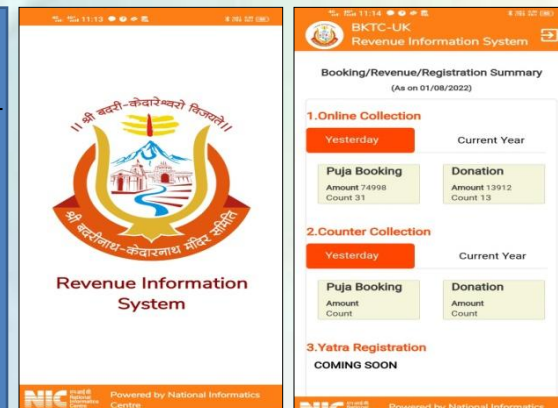
राजस्व सूचना प्रणाली ऐप

बीकेटीसी और सरकार के लिए

-दैनिक ऑनलाइन और
काउंटर आय

- मंदिर में दैनिक यात्री पंजीकरण और हेडकाउंट

- दैनिक नकद व अन्य भेंट की सचना सीधे मंदिरों से



2019 से सेवा में

उद्धाटन हेतु उपलब्ध

तोशखाना | थाली भेंट काउंटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम
यात्री ऐप | राजस्व सूचना प्रणाली ऐप

भविष्य में किये जाने वाले कार्य

- ऑफिस का ऑटोमेशन
- eHRMS
- स्मार्ट काउंटर



आशा संगिनी प्रणाली

<https://asha.uk.gov.in>

वेब आधारित प्रणाली

आशा कार्यकर्ताओं को समय पर पारदर्शी रूप से भुगतान की व्यवस्था

आशा संगिनी दूत मोबाइल ऐप

नागरिकों के लिए आशा कार्यकर्ताओं से सीधे सेवा प्राप्ति का एक माध्यम

आशा संगिनी मोबाइल ऐप

आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की सीधे फील्ड से रिपोर्टिंग



आशा डायरी

आशा डायरी का
ऑटोमैटिक जनरेशन

गांव की स्वास्थ्य प्रोफाइल

गांव की स्वास्थ्य प्रोफाइल का
ऑटोमैटिक जनरेशन

आशा सहायक मोबाइल ऐप

आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करने और उन्हें समय पर बकाया राशि प्राप्त करने में मदद करने के लिए आशा सहायक हेतु ऐप

ए एन एम मोबाइल ऐप

आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करने और उन्हें समय पर बकाया राशि प्राप्त करने में मदद करने के लिए ए एन एम हेतु ऐप

आशा संगिनी हेल्प डेस्क

आशा संगिनी प्रणाली के बारे में मार्गदर्शन करने और आशा कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब देने के लिए समर्पित हेल्पडेस्क

नवंबर 2022 से
सेवा में

मुख्य
विशेषताएं

- पीएफएमएस के साथ Integrated रा० सू० वि० के० उत्तराखंड की प्रथम प्रणाली
- फील्ड से काम की रीयल टाइम रिपोर्टिंग

SUSTAINABLE TRANSPORT AND EFFICIENT MOBILITY SOCIETY

STEMS MEGHALAYA

An Initiative by the Government of Meghalaya



Ride With a Smile

STEMS 2022 में मेघालय सरकार द्वारा स्थापित एक सोसाइटी है, जो सुरक्षित, टिकाऊ, कुशल और लागत प्रभावी आधुनिक परिवहन समाधानों का लाभ उठाकर लोगों के आवागमन के तरीके में क्रांति लाने के लिए है। सोसाइटी का उद्देश्य परिवहन समाधानों को विकसित और कार्यान्वित करना है जो गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं, भीड़भाड़ को कम कर सकते हैं और उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण को लाभ पहुंचा सकते हैं।

NIC उत्तराखंड का **STEMS सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट** अपने प्रकार की अनूठी प्रणाली है जिसका उद्देश्य STEMS सोसाइटी के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक प्रभावी टूल उपलब्ध करवाना है

प्रमुख घटक

वेब पोर्टल

प्रबंधन , मॉनिटरिंग एवं संचालन :

- पंजीकरण अनुरोध प्रसंस्करण
- बस पास जारी करना
- मास्टर डेटा
- Duty Allocations
- Payment गेटवे प्रबंधन

मोबाइल ऐप

- छात्र पंजीकरण ऐप- छात्र पंजीकरण, बस पास जारी करने, ट्रेकिंग के लिए
- केयर टेकर - यात्रा प्रबंधन के लिए

वीएलटी आधारित बस मूवमेंट मॉनिटरिंग

जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली

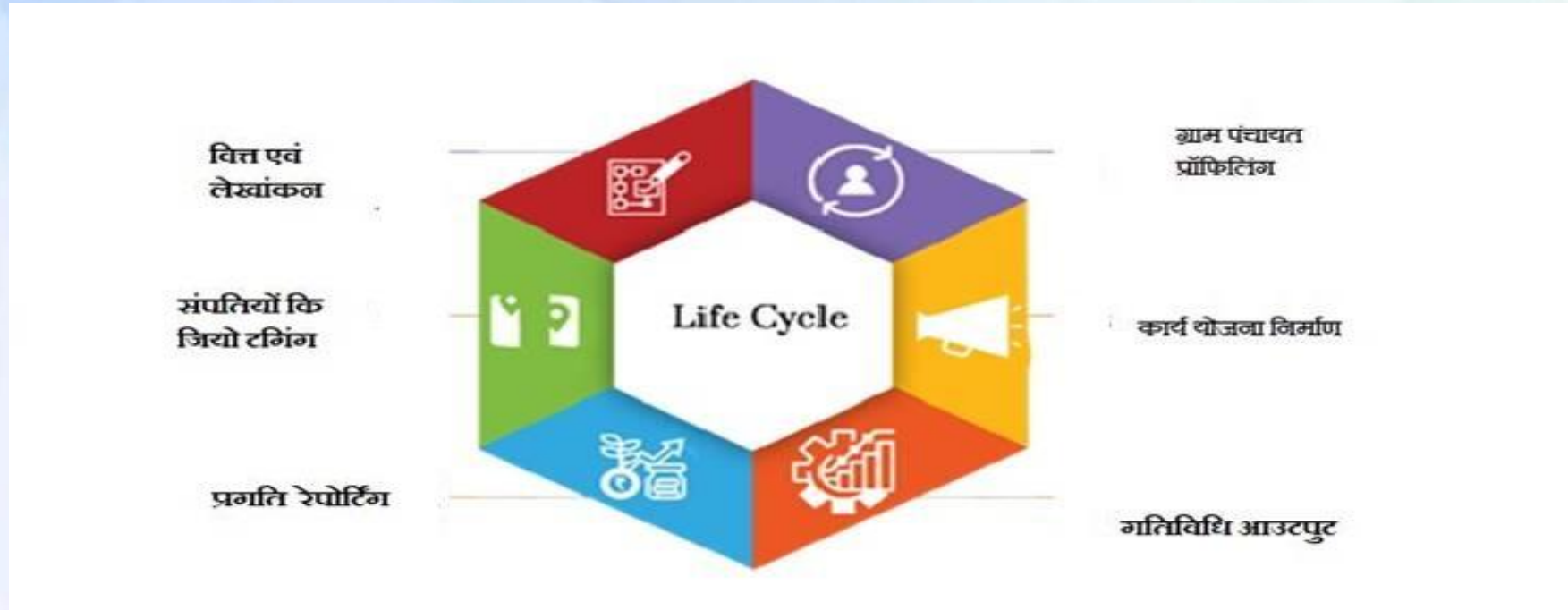
मई 2023
से प्रारम्भ

भविष्य में किये
जाने वाले कार्य

केयर टेकर ऐप | मास्टर एंट्री मॉड्यूल | रिपोर्ट | विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड

- पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय योजना है।
 - इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को ₹ 6000 / - प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी।
 - योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
 - राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।
 - फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा।
 - योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियां हैं।
-
- | | |
|---|--------|
| • उत्तराखंड राज्य के पंजीकृत किसानों की संख्या | 970291 |
| • उत्तराखंड राज्य के किसानों की संख्या जिन्हें 13 वीं (2022-23 दिसम्बर-मार्च) किश्त प्रदान की जा चुकी है | 787576 |

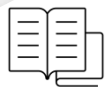
पंचायती राज के लिए सरलीकृत कार्य आधारित अकाउन्टिंग अनुप्रयोग



स्थिति -उत्तराखंड

कुल ग्राम पंचायतें	7795
प्रकाशित वार्षिक योजनाओं(जीपीडीपी) ग्राम पंचायतों की संख्या 2022-2023	7782
जीओ-टैगिंग प्रारंभ करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या	7788
लेखा माह बंद ग्राम पंचायतों की संख्या	7777
पीएफएमएस एकीकरण के साथ ग्राम पंचायतों की संख्या	7791

01



राशन कार्ड प्रबंधन
प्रणाली
(आर.सी.एम.एस)

2333932

कुल राशन कार्ड

AAY - 175752
PHH - 1202139
SFY - 956041

95,47,365

कुल लाभार्थी

एक देश एक राशन
कार्ड

2922 Transaction

02



पीडीएस खाद्यान्न का
एफपीएस स्तर तक
आवंटन

3,34,548

कुल आवंटन

चावल - 2,07,420 (Qtls)

गेहूँ - 1,27,128 (Qtls)

आरसी डाटाबेस
आयुष्मान भारत
योजना के साथ
एकीकृत

03



आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

एफसीआई डिपो - 21

बेस डिपो - 23

आंतरिक डिपो - 173

आरसी डाटाबेस
डिजिटलॉकर के साथ
एकीकृत

04



उचित मूल्य दुकान
का ऑटोमेशन

9057

कुल एफपीएस

2349518

मासिक लेनदेन

पीएमजीकेवाई



6
ऑन-बोर्ड किए गए कुल अस्पताल
e-Hospital(4) और Nextgen e-Hospital(2)

1,23,283
ORS पर कुल पंजीकरण

90,02,641
कुल transactions सितम्बर,
२०१५ से

9767
कुल ABHA बनाये

35459
कुल ABHA स्वास्थ्य रिकॉर्ड
से लिंकड

उत्तराखंड के कारागार कार्यालयों में डिजिटल नवाचार

1

8

2

11

75252

6824

203303

34

केंद्रीय
कारागार

जिला
कारागार

उप
कारागार

ऑन-बोर्ड
कारागार

पंजीकृत
कैदी

कारागार
के अंदर
कैदी

पंजीकृत
मुलाकाती

विशेष
छूट वाले
कैदी

प्रमुख सेवाएं

कैदी प्रवेश
प्रबंधन

न्यायालय
प्रबंधन

गेट प्रबंधन

कैदियों की सजा
प्रबंधन

कैदी व्यक्तिगत
प्रबंधन

रिपोर्ट प्रबंधन

कैदी पुनर्वास
मॉड्यूल

विशेष छूट

प्रमुख विशेषताएँ

वेब सक्षम
प्रणाली

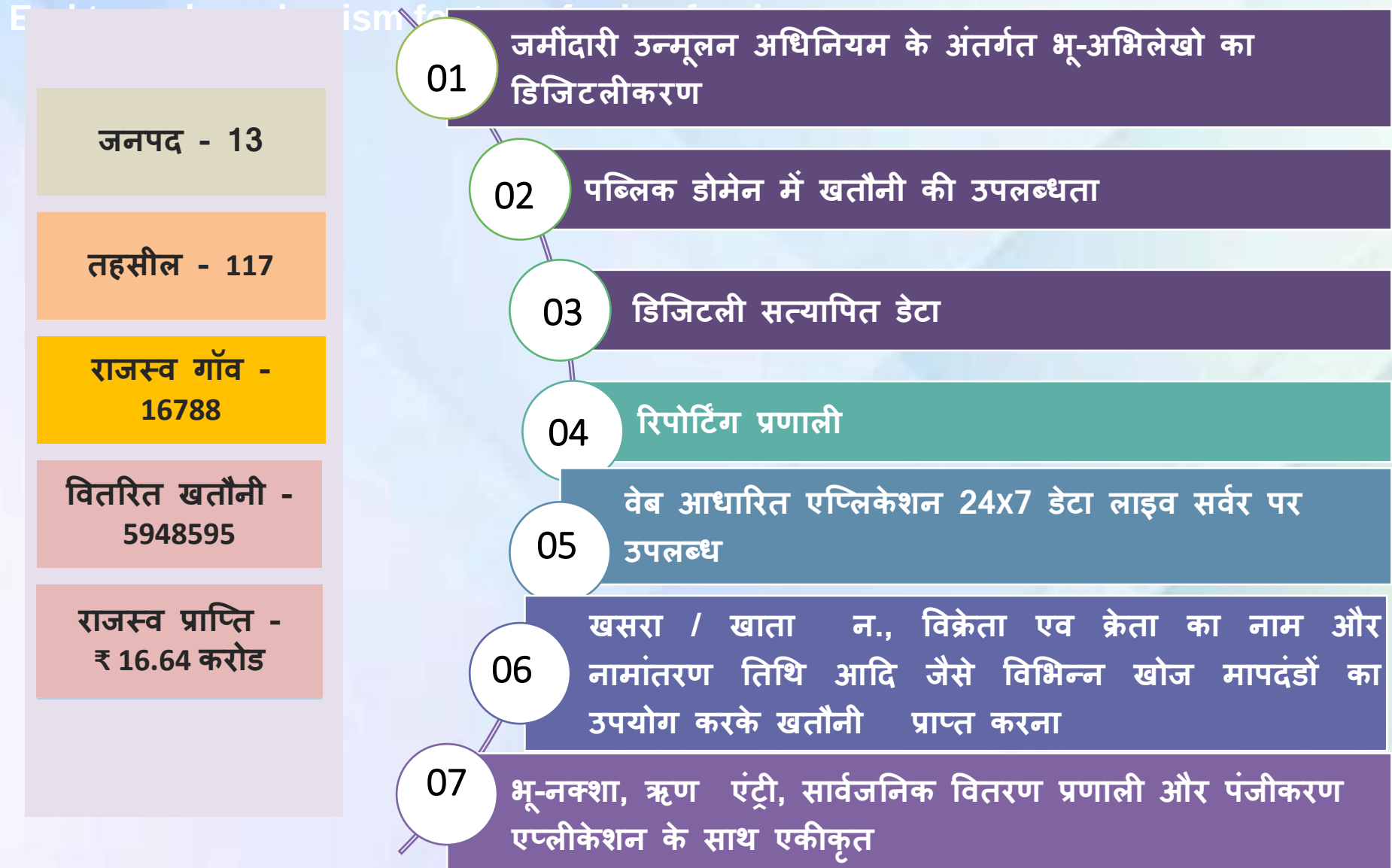
आगंतुक
पंजीकरण

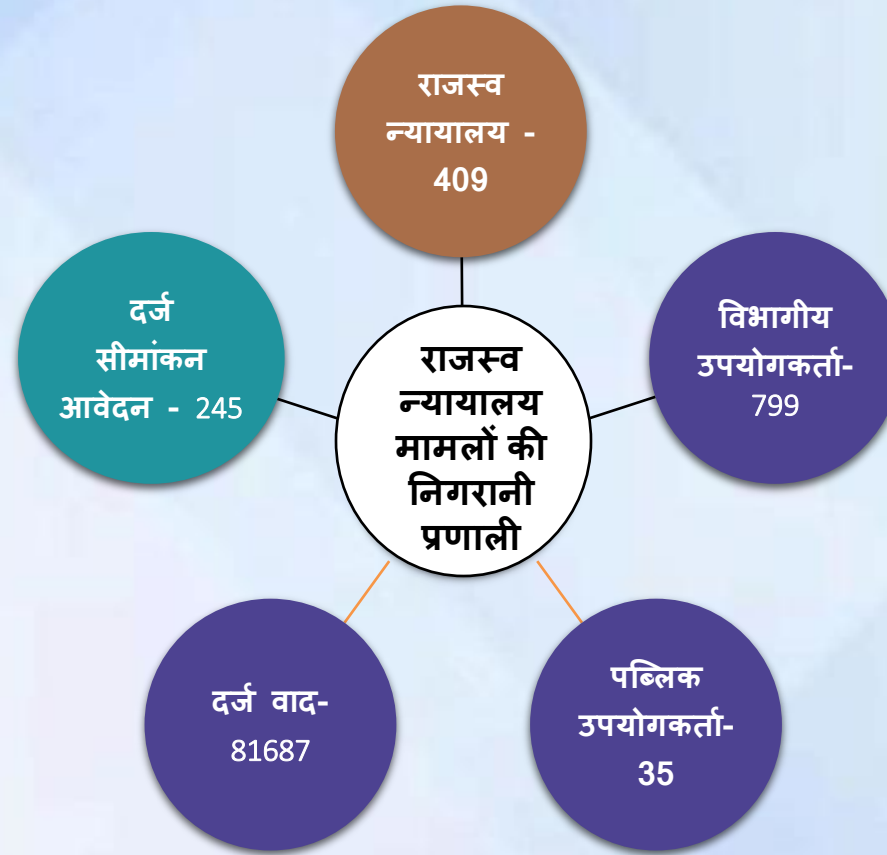
ई मुलाकात के
लिए पंजीकरण

भूमिका आधारित
डैशबोर्ड

एस०एम०एस०
एवं ई-मेल
अलर्ट

रिपोर्ट खोज
सुविधा





प्रमुख विशेषताएँ

वेब सक्षम प्रणाली	भूमिका आधारित एप्लीकेशन
ऑनलाइन भुगतान सुविधा	ई-समन सुविधा
G2C और G2G सेवा	सभी स्तरों पर लम्बित आवेदन देखने की सुविधा
रिपोर्ट सुविधा	रोल आधारित डैशबोर्ड

उत्तराखण्ड राज्य में दर्ज राजस्व वादों का विवरण

81773

दर्ज वाद



45163

लम्बित वाद



36610

बंद वाद



2

आज दर्ज हुए वाद



जनपद-13

तहसील-115

राजस्व गाँव -
7455

तैयार स्वामित्व
दस्तावेज-
269705

वितरित
स्वामित्व
दस्तावेज-
143127

राजस्व प्राप्ति-
₹ 28.63लाख

01 ग्रामीण आबादी भूमि क्षेत्र का डिजिटलीकरण

02 व्यक्तिगत संपत्ति की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए ड्रोन तकनीक और सैटेलाइट मैपिंग का उपयोग

03 ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण

04 ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम करना

05 डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित डेटा

06 संपत्ति के मालिक ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभों के लिए पात्र

07 डिजिलॉकर के साथ एकीकृत

भूमि उपयोग परिवर्तन (धारा-143/144) और भूमि खरीद (धारा-154) आवेदन अनुमति का डिजिटलीकरण



प्रमुख विशेषताएँ

वेब सक्षम प्रणाली

भूमिका आधारित एप्लीकेशन

सिंगल विंडोज सिस्टम के साथ एकीकृत

उचित रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स सिस्टम

G2C और G2G सेवा

सभी स्तरों पर लम्बित आवेदन देखने की सुविधा



एकाधिक वेबसाइटों को प्रबंधित करने के लिए एकल इंटरफ़ेस। सभी वेबसाइटों से समेकित जानकारी एकल पोर्टल (राज्य पोर्टल) पर प्रदर्शित।

स्टेट पोर्टल राज्य सरकार की सभी सूचनाओं, सेवाओं, योजनाओं आदि के लिए सिंगल गेटवे।

सभी विभागों की सामग्री की अद्यतन स्थिति देखने के लिए प्रबंधक के लिए डैशबोर्ड सुविधा।

वेबसाइट निर्माण के विभिन्न चरण

विभाग द्वारा वेबसाइट के लिए अनुरोध

राज्य प्रबंधक द्वारा स्वीकृति एवं पासवर्ड का निर्माण

विभाग द्वारा थीम और अद्यतन सामग्री का चयन

सुरक्षा ऑडिट और डोमेन पंजीकरण के बाद वेबसाइट का शुभारंभ

वेबसाइट पर अपडेट की गई सामग्री राज्य पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित

कार्यान्वयन की स्थिति

1.

• 8 वेबसाइट लाइव कर दी गई हैं

2.

• 20 वेबसाइट विकास के अधीन हैं

ई-ग्रंथालय भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सरकारी पुस्तकालय की उपलब्धता का डिजिटल मंच है। ई-ग्रंथालय पारंपरिक पुस्तकालय को ई-पुस्तकालय में बदलने में सहायक है।

प्लेटफॉर्म के तहत, एनआईसी अनुरोध के आधार पर सरकारी लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी मॉड्यूल और क्लाउड होस्टिंग सुविधा के साथ लाइब्रेरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रदान करता है।

उत्तराखंड राज्य में ई-ग्रंथालय की स्थिति

ई-ग्रंथालय URL: <https://eg4.nic.in/ukhed/OPAC/Default.aspx>

कुल शीर्षक
491425

कुल सूची
अभिलेख
1713172

कुल सदस्य
108042

कुल पुस्तकालय
116

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के पश्चात संख्यात्मक दृष्टि से प्रदेश में उच्च शिक्षा का द्रुतगति से विकास हुआ है।

ई-ग्रंथालय 4.0 को राज्य के 5 राजकीय विश्वविद्यालयों, 01 राजकीय विश्वविद्यालय परिसर व 106 राजकीय महाविद्यालयों तथा 03 अनुदानित महाविद्यालयों में लागू किया गया है

इसका उपयोग ऑनलाइन डेटा प्रविष्टि और संचालन के लिए किया जाता है

यह क्लस्टर MOPAC - Mobile Responsive OPAC और e-Granthalaya Mobile App का उपयोग करके पुस्तकालय सदस्यों को सार्वजनिक डोमेन और डिजिटल लाइब्रेरी सेवाओं में ई-कैटलॉग की सुविधा प्रदान करता है।

01

महाविद्यालय
70

02

स्नातकोत्तर
महाविद्यालय
36

03

अनुदानित
महाविद्यालय
03

04

विश्वविद्यालय
06



उत्तराखण्ड शासन



67
सचिव

178
विभाग के प्रमुख

2775
आहरण और वितरण अधिकारी अधिकारी

178
विभाग

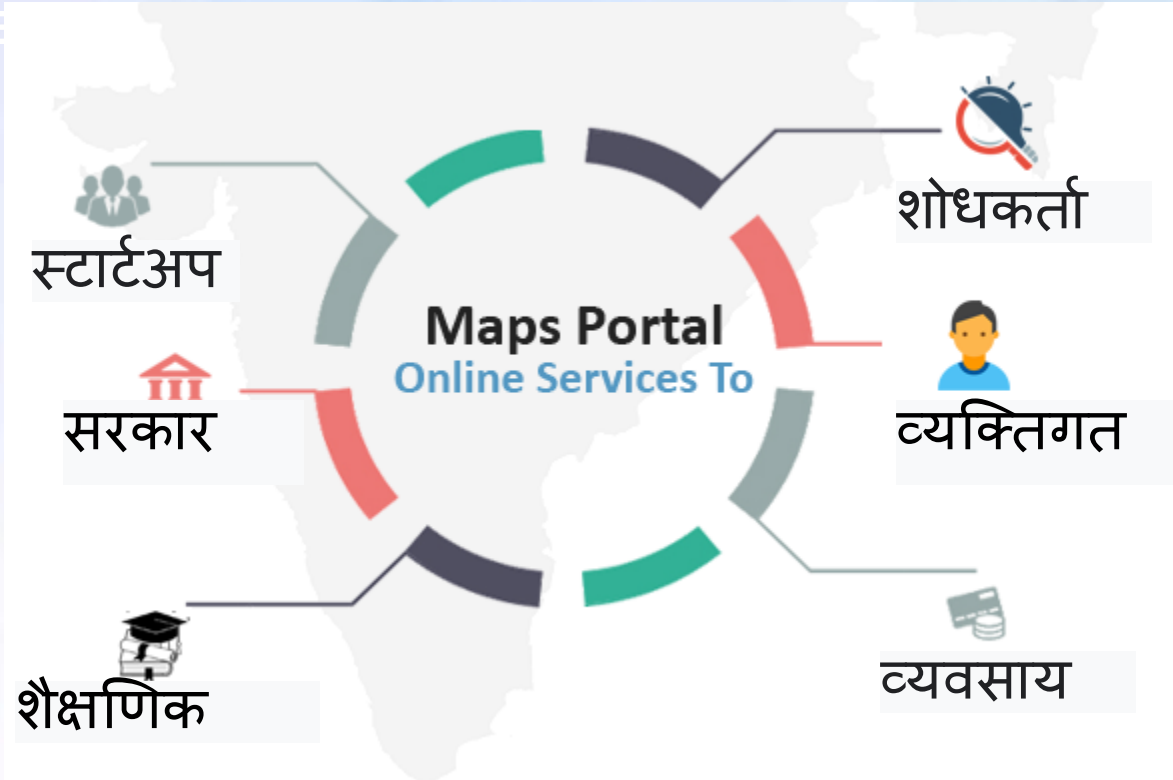
5963
कुल योजनाएं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन (वीएलटीडी) लगाने को अनिवार्य करते हुए नियम 125एच को शामिल करके सीएमवीआर में संशोधन किया

❖ सार्वजनिक सेवा वाहनों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए.

❖ संकट में मदद के लिए सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग और कई आपातकालीन बटन (वीएलटीडी) से लैस उपकरण





Online Maps Services

Survey of India

<https://onlinemaps.surveyofindia.gov.in>

Hon'ble Prime Minister After announcing new map policy

"It is a massive step. Our government has taken a decision that will provide a huge impetus to Digital India. Liberalising policies governing the acquisition and production of geospatial data is a massive step in our vision for an Atmanirbhar Bharat"

Shri Narendra Modi, Prime Minister of India



एक बार पंजीकरण

4000+ टोपोशीट्स
की सूची

मानचित्रों के
विभिन्न प्रारूप

ऑनलाइन बिक्री

भारतकोष पेमेंट
गेटवे

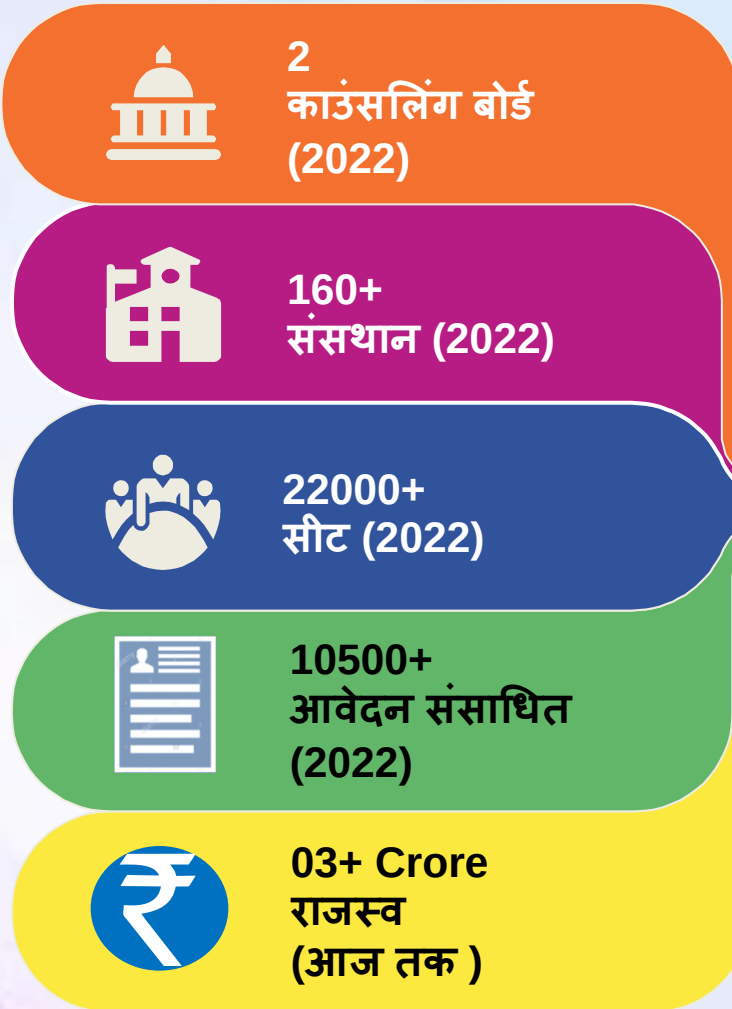
प्रोजेक्ट - ई-आफिस
संचालन - वर्ष 2020 से

संक्षिप्त विवरण - उत्तराखंड कई सचिवालय , निदेशालयों व जनपदों में ई-आफिस का संचालन

संक्षिप्त सांख्यिकी - उत्तराखंड के सचिवालय व अन्य कार्यालयों में ई-आफिस के माध्यम से लगभग 1,75,000 ई-पत्रावली सृजित की जा चुकी है । उक्त ई-फाइलों पर टीप /टिप्पणी व पत्र से सम्बंधित अधिकांशतः कार्य देवनागरी लिपि में किया जा रहा है । उत्तराखंड सचिवालय में 95% कार्य ई-पत्रावलियों पर सरलतापूर्ण किया जा रहा है । आवश्यकतानुसार ई-आफिस से सम्बंधित तकनीकी समस्याओं हेतु उपयोगकर्ताओं को सहयोग प्रदान किया जाता है ।

रोड मैप – निदेशालयों व अन्य विभागों में भी ई-आफिस से सम्बंधित कार्य प्रगति पर है ।

ई-काउंसलिंग उत्तराखंड के शैक्षणिक संस्थानों को काउंसलिंग और प्रवेश के लिए प्रदान की जाने वाली एक वेब आधारित सेवा है



ई-काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो डायग्राम



देश में उपभोक्ता फोरम का कम्प्यूटरीकरण और कंप्यूटर नेटवर्क

कन्फोनेट एक इंटरनेट आधारित केस मॉनिटरिंग सिस्टम है जो केस के पंजीकरण से लेकर निर्णय होने तक, उपभोक्ता मंचों के कार्य प्रवाह को स्वचालित करने के लिए विकसित किया गया है

उद्देश्य

परियोजना का उद्देश्य, पूरे भारत में उपभोक्ता निवारण मंचों पर परिचालन दक्षता, समन्वय, कहीं से और कभी भी, न्यायिक प्रशासन में गति और उपभोक्ता फोरम पर सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का बुनियादी ढांचा विकसित करना है। इसका उद्देश्य :

- ई- शासन
- क्षमता
- पारदर्शिता
- व्यवस्थित ढंग से कार्य करना
- उपभोक्ताओं को समयबद्ध न्याय दिलाना

वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़े

पंजीकृत मामले	निस्तारित मामले	बकाया मामले	केस निस्तारण दर
20090	14121	6115	70 %

वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़े

पंजीकृत मामले	निस्तारित मामले	बकाया मामले	केस निस्तारण दर
22876	16915	6169	73.28%

उद्देश्य - उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए "ई-दाखिल पोर्टल"

उद्देश्य और लाभ

- पोर्टल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक मंच प्रदान करना है ।
- पोर्टल नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अनुसार शिकायतों को आसानी से और तेजी से दर्ज करने के लिए वन स्टॉप विंडो के रूप में कार्य करता है।
- पोर्टल का उद्देश्य इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए सभी पहलुओं को शामिल करना है ।
- यह शिकायत निवारण तक शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में पूरी पारदर्शिता प्रदान करता है
- पोर्टल में विभिन्न उपयोगकर्ता नियमावली और वीडियो ट्यूटोरियल भी शामिल हैं जो इसे उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच बनाते हैं ।
- विभिन्न उपयोगी लिंक के अलावा, शिकायत दर्ज कराने वाले उपभोक्ता/अधिवक्ता पोर्टल पर किसी भी समय समस्या होने पर हेल्प डेस्क से भी जुड़ सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- नया उपभोक्ता मामला दर्ज करें
- शुल्क का ऑनलाइन भुगतान
- संबंधित शिकायतकर्ताओं और उत्तरदाताओं को ई-नोटिस
- एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट

आवेदन प्रवाह



नागरिक /
अधिवक्ता
पंजीकरण

लॉग इन

शिकायत
दर्ज करें

केस विवरण दर्ज
करें और सहायक
दस्तावेज अपलोड
करें

शुल्क भुगतान
और जमा करें



राज्य कर विभाग उत्तराखंड हेतु एक जीएसटी पोर्टल विकसित किया गया है जो उत्तराखंड के सभी डीलरों के लिए सिंगल विंडो के रूप में काम करता है। पोर्टल, डीलरों को सभी वैट और जीएसटी सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है तथा अधिकारियों को जीएसटी डाटा से सम्बंधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करता है। इस पोर्टल में लॉगिन आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

यूआरएल : <https://gst.uk.gov.in>

इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध की गई कुछ रिपोर्ट और मॉड्यूल निम्न प्रकार हैं :

पंजीकृत डीलर को उनके टर्नओवर के आधार पर या और अन्य कारणों से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करना

- पंजीकृत डीलर आधारित विभिन्न प्रकार की विश्लेषणात्मक रिपोर्टें
- संयुक्त आयुक्त के लिए निगरानी प्रणाली: संयुक्त आयुक्त/समीक्षा अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्राधिकारी अधिकारियों की रेड फ्लैग रिपोर्ट देखने में सक्षम है तहत क्षेत्राधिकारी अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा भी कर सकते हैं
- आयुक्त के लिए निगरानी प्रणाली: क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित संपूर्ण रिपोर्ट
- अधिकारियों और संयुक्त आयुक्तों को आयुक्त डैशबोर्ड, आयुक्त में प्रदर्शित किया जाता है
- क्षेत्राधिकारी अधिकारियों के साथ-साथ संयुक्त आयुक्तों की भी समीक्षा कर सकते हैं

पंजीकरण

ट्रिपशीट और
ट्रांजिट पास

वार्षिक और त्रैमासिक
वापस करना

वैट के लिए एमआईएस
रिपोर्ट

कर का ई-भुगतान

एमआईएस रिपोर्ट
से जीएसटी डेटा

जीएसटी-प्राइम
कार्यान्वयन

अधिकारियों का स्थानांतरण
के लिए ऑनलाइन सिस्टम

लाभार्थी (नागरिक , पंजीकृत डीलर , राज्य कर विभाग):

विभाग के अधिकारी, वैट डीलर और जीएसटी डीलर

अभी तक प्रदान की गई सेवाएं

इस पोर्टल को केदारनाथ धाम को जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक द्वारा गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी के हेलीपैड से केदारनाथ के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टिकट दरों पर टिकट बुक किए जा सकते हैं। साथ ही यह सुविधा पंजीकृत टूर ऑपरेटर को भी प्रदान की गयी है जो अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से यात्रियों के समूह की टिकट बुक कर सकते हैं

प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी को कम करना है क्योंकि पोर्टल पर टिकट की उपलब्धता और सभी हेलीपैड से किराए के बारे में स्पष्टता होगी।

मोबाइल एप्लिकेशन - क्यूआर कोड टिकट का सत्यापन और मोबाइल ऐप का उपयोग करके हेलीपैड पर बोर्डिंग पास जो पोर्टल पर वेब सेवा से डेटा की पुष्टि करता है।

ओटीपी आधारित पंजीकरण

ई-टिकट

विशेषताएँ

यात्री को एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजी जाती है

रिफंड की सुविधा

काउंटर आधारित स्थापित करना

लाभार्थी

- यूकाडा - सुपर एडमिन
- GMVN - वर्किंग एंड कंट्रोलिंग एजेंसी
- ऑपरेटर्स - टिकट बुक करें और टिकट की स्थिति की जानकारी
- ट्रेवल एजेंट - टिकट बुक
- नागरिक - टिकट बुक कर सकते हैं

यूआरएल

<https://heliservices.uk.gov.in>

:

Slide Number 38

यह पोर्टल नागरिकों को इन योजनाओं के तहत ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया था। यह एक कार्यप्रवाह आधारित प्रणाली है जिसके माध्यम से आवेदक हमारे पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करता है और फिर आवेदन को डीटीडीओ द्वारा अनुमोदित किया जाता है और सूचना को संबंधित बैंक को भेजा जाता है जहां इस पोर्टल के माध्यम से राशि/ऋण स्वीकृत किया जाता है।

यूआरएल : <https://vcsgscheme.uk.gov.in>

प्रमुख विशेषताएँ

- इसके तहत सभी योजनाओं के तहत ऑनलाइन पंजीकरण।
- ऋण प्रदान करने तक योजना पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए प्रवाह आधारित प्रणाली।
- एसएमएस सेवाओं का उपयोग आवेदन की स्थिति भेजने के लिए किया जाता है।
- आवेदन की स्थिति की जांच करने और अनुमोदन करने के लिए बैंक के लिए उपयोगकर्ता लॉगिन।

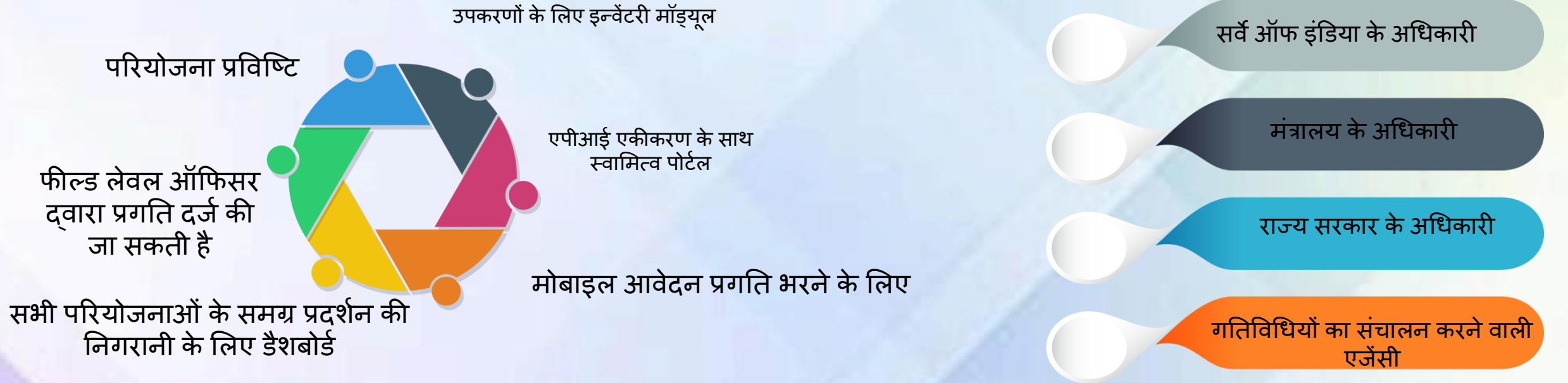
लाभार्थी

- सुपर एडमिन - पर्यटन विभाग
- डीटीडीओ - जिला पर्यटन विकास अधिकारी
- डीएलटीएफसी - जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी
- एसएलबीसी - राज्य स्तरीय बैंक समिति
- भारतीय रिजर्व बैंक
- बैंक नियंत्रण प्रमुख - प्रत्येक एकीकृत बैंक के लिए एक
- बैंकों की सभी शाखाएं
- नागरिक



यूआरएल : <https://pragati.surveyofindia.gov.in>

यह विभाग में चल रही प्रत्येक परियोजना के तहत अपनी सभी गतिविधियों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए भारत के सर्वेक्षण द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रवाह आधारित प्रणाली है। परियोजनाओं को मुख्यालय स्तर पर सिस्टम में दर्ज किया जाता है और फिर विभिन्न जीडीसी या राज्यों को सौंपा जाता है। सभी निर्देशक जीडीसी सौंपी गई परियोजना की सभी गतिविधियों के प्रभारी बना सकते हैं, आगे प्रभारी ने कई ऑपरेटरों/अधिकारियों को कार्य सौंपा। प्रगति तब उनके द्वारा भरी जाती है। समग्र प्रदर्शन/प्रगति को कैप्चर किया जाता है और सुचारु निगरानी से डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है।



वाहन 4 व सारथी 4

वाहन और डीएल से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं वाहन और सारथी का कार्यान्वयन।

एम - वाहन

मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल आधारित प्रणाली

नागरिक केंद्रित सेवाएं

आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी, स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में परिवर्तन, ऑनलाइन परमिट, फिटनेस, एलएल/डीएल, कर भुगतान, आदि

फैंसी नंबर नीलामी

पंजीकरण के फैंसी चिह्न प्राप्त करने के लिए फैंसी नंबर नीलामी प्रणाली का कार्यान्वयन।

सीएससी के माध्यम से सेवाएं

मामूली शुल्क के साथ राज्यों में पंजीकृत सीएससी के माध्यम से वाहन/सारथी ऑनलाइन सेवाओं का कार्यान्वयन।

राज्य स्तरीय पहल

चारधाम जाने वाले वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीनकार्ड जारी करने की प्रणाली और कोविड महामारी के दौरान चालक/परिचालक/क्लीनर डेटा एकत्र करना.

डीलर प्वाइंट सिस्टम

वाहन पंजीकरण के लिए उत्तराखंड के सभी डीलरशिप में डीलर प्वाइंट सिस्टम लागू करना।

ई-चालान

परिवहन एवं यातायात विभाग में मोबाइल आधारित प्रवर्तन समाधान का कार्यान्वयन

अन्य कार्यान्वयन

प्रदूषण परीक्षण केंद्रों से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र और प्रवेश कर के संग्रह के लिए ऑनलाइन चेकपोस्ट मॉड्यूल।



अत्यावश्यक मांग के लिए
अस्पतालों के लिए एसओएस
विकल्प

वार रूम द्वारा मांग को संशोधित
करना

अर्ध नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं की प्रगति की निगरानी - विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजना।

योजना की संरचना वार प्रगति निगरानी। पोर्टल के साथ एकीकृत नलकूपों से निश्चित समय अंतराल पर डेटा की प्राप्ति। ऑटोमैटेड मीटर रीडर्स (एएमआर) से मीटर रीडिंग।

अर्ध नगरीय क्षेत्रों की 22 योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है।

उपभोक्ता के लिए मोबाइल ऐप।
सी.एस.सी. के साथ एकीकृत।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) से जुड़ा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) का अनुपालन।

लगभग 90 लाख उपभोक्ता।
114 बिलिंग केंद्र।

खान मालिक, स्टोन क्रशर और स्टॉकिस्ट का पंजीकरण

ई-रवन्ना (ट्रिपशीट) निर्गत किया जाना

प्रति दिन 12000 ई-रवन्ना निर्गत

प्रशासन, शिक्षकों, छात्रों, नागरिकों और विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड के अन्य हितधारकों के लिए एक एकीकृत मंच



आंकड़ों का सारांश

- कार्यान्वित: 2016
- शिक्षक/कर्मचारी प्रोफाइल: 70000 (लगभग)
- स्कूल : 22000 (लगभग)
- नियंत्रण कार्यालय: 290
- छात्र नामांकन: 10 लाख (लगभग)

इंटरफेस

- वेब व्यू
- जीआईएस व्यू
- मोबाइल एप्लिकेशन
- डेटा विश्लेषण
- ग्राफिकल एवं टेक्स्टुअल एमआईएस रिपोर्ट

ई-सेवाएं

- ई-सर्विस बुक
- स्कूल निर्देशिका एवं कोटिकरण
- शिक्षक का स्थानांतरण मॉड्यूल
- स्कूल का ई- निरीक्षण
- अतिथि शिक्षक भर्ती
- शिक्षक सेवा विस्तार
- लर्निंग एंड शेयरिंग
- शिक्षक दस्तावेज़ सत्यापन
- छात्र के मासिक मूल्यांकन, सीखने के परिणाम और शिक्षक के प्रदर्शन के लिए दक्ष डैशबोर्ड
- शिक्षकों द्वारा एसीआर का ऑनलाइन सबमिशन

सेवाएं (कोविड 19)

- ई-सामग्री आधारित शिक्षा/शिक्षण
- छात्र प्रवेश प्रश्न
- पोर्टल के माध्यम से सृजित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सीएमएस आधारित वेबसाइटें (195)

वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई.सी.एफ.आर.ई), देहरादून, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान के द्वारा सभी वन प्रभागों में विभिन्न वन वनस्पतियों के तहत ऑनलाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने पर एक परियोजना लागू किया जा रहा है। एफआरआई देहरादून, आई.सी.एफ.आर.ई देहरादून, वन संस्थान, वन प्रभाग और देश भर के नागरिक इस सेवा के हितधारक हैं।

सारांश और फैलाव क्षेत्र

दिसंबर 2022
में शुरू किया
गया

9
संस्थान

37
राज्य

830 (लगभग)
वन प्रमंडल

1000 (लगभग)
सैंपलिंग साइट्स

प्रमुख प्रक्रिया

- वन मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मिट्टी की गुणवत्ता को मापने के लिए रिपोर्ट कार्ड हैं
- नमूना स्थलों से नमूना संग्रह
- 12 पोषक तत्वों, थोक घनत्व और कूड़े के नमूनों (बल्क डेंसिटी एवं लिटर) का प्रयोगशाला परीक्षण
- मानक मूल्य की राज्यवार गणना
- परीक्षण मूल्य की वन प्रमंडलवार गणना
- जैविक और अकार्बनिक उर्वरक हेतु सुझाव
- वन प्रमंडलवार मृदा स्वास्थ्य कार्ड का निर्माण

एनआईसी उत्तराखण्ड मिनी क्लाउड, मिनी डाटा सेंटर, नेशनल क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी सेवाएं

आधारभूत संरचना

- ✓ 15 Rack का डाटा सेंटर
- ✓ VmWare आधारित Cloud
- ✓ Load Balancers
- ✓ WAF

राज्य और केंद्र सरकार की 110 से अधिक
वेबसाइटों की hosting एवं support

उपलब्ध सेवाएं

1. Collocation सेवा
2. Audit & Staging सेवा
3. Managed Hosting सेवा
4. Application Load Testing सेवा
5. SVN सेवा
6. वेब सर्वर/डेटाबेस के लिए Support
7. सर्वर प्रबंधन

साइबर सुरक्षा सेवाएं

1. ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग
2. NIC में होस्टेड वेबसाइट का Vulnerability Assessment
3. Application Security हेतु Support
4. CSD Clearance & Website Audit by NIC HQ हेतु Support
5. Cert-In द्वारा रिपोर्ट किये गए Incidence की मॉनिटरिंग

कनेक्टिविटी

- १० Gbps Uplink चंडीगढ़ (रेलटेल) , लखनऊ (पावर ग्रिड) एवं दिल्ली(बीएसएनएल)
- राज्य मुख्यालय से १३ जिला केन्द्रों के मध्य ३४ Mbps/१०० Mbps/१ Gbps की connectivity.
- NKN प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ४० विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार के संस्थानों, विश्वविद्यालयों के मध्य १०० Mbps/१ Gbps /१० Gbps की connectivity.
- NKN PoP ISO 27001:2013 प्रमाणित है
- NKN के अन्तर्गत प्रथिस्तित राजकीय संस्थान - LBSNAA मसूरी, IGNFA देहरादून, IMA देहरादून, ICFRE देहरादून, AIIMS ऋषिकेश, IIT रुड़की, ITBP अकादमी मसूरी
- NKN का २४ X ७ संचालन
- 24 X 7 नेटवर्क संचालन के लिए 10 सदस्यीय FMS टीम वर्तमान में M/s Ebixcash द्वारा प्रदान की गई है
- प्रगति प्रोजेक्ट के तहत वीसी सपोर्ट के लिए 1 FMS.

सेवाएं

- **ईमेल** - gov.in डोमेन में लगभग हर महीने 700 नए ईमेल-आईडी बनाए जाते हैं।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** - औसतन 150 वीसी प्रति माह, 5-10 अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा, 1--20 अध्यक्षता मुख्य सचिव द्वारा
- **सर्विस डेस्क** - एफएमएस द्वारा प्रतिदिन औसतन 60 टिकट बनाए और सुलझाए जाते हैं
- **इंटरनेट और इंट्रानेट से संबंधित सेवाएं :-**
 - मुख्य कार्यालय
 - जिला समाहरणालय (– 1200 Nodes)
 - राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा, भारतीय सर्वेक्षण और अन्य केंद्र
 - सरकार एवं राज्य सरकार के विभाग

सेवाएं जारी

- उत्तराखंड के लिए AEBAS समन्वय, 251 राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय (सचिवालय सहित) AEBAS प्रणाली में शामिल
- आईटी विभाग , उत्तराखंड सरकार की तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य,
- राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय को आईसीटी अवसंरचना समर्थन/परामर्श।